जुलाई 2021 ₹ 20

समाजवादी बुलेटिन

मोदी सरकार में महंगाई से जनता त्रस्त 41 चार सूत्रों में समाजवादी सरोकार 30

जनमत पर डाका 16

R.N.I. No. 68832/97

समाजवादी आंदोलन भेदभाव मिटाने के लिए है। समाजवादी पार्टी को यह दायित्व निभाते रहना है। हमें महिलाओं, युवाओं, गरीबों और किसानों की बेहतरी के लिए काम करना होगा। सभी वर्गों ने समाजवादी पार्टी का साथ दिया है। हमें सभी को साथ लेकर चलना है।

मुलायम सिंह यादव
संस्थापक-संरक्षक, समाजवादी पार्टी

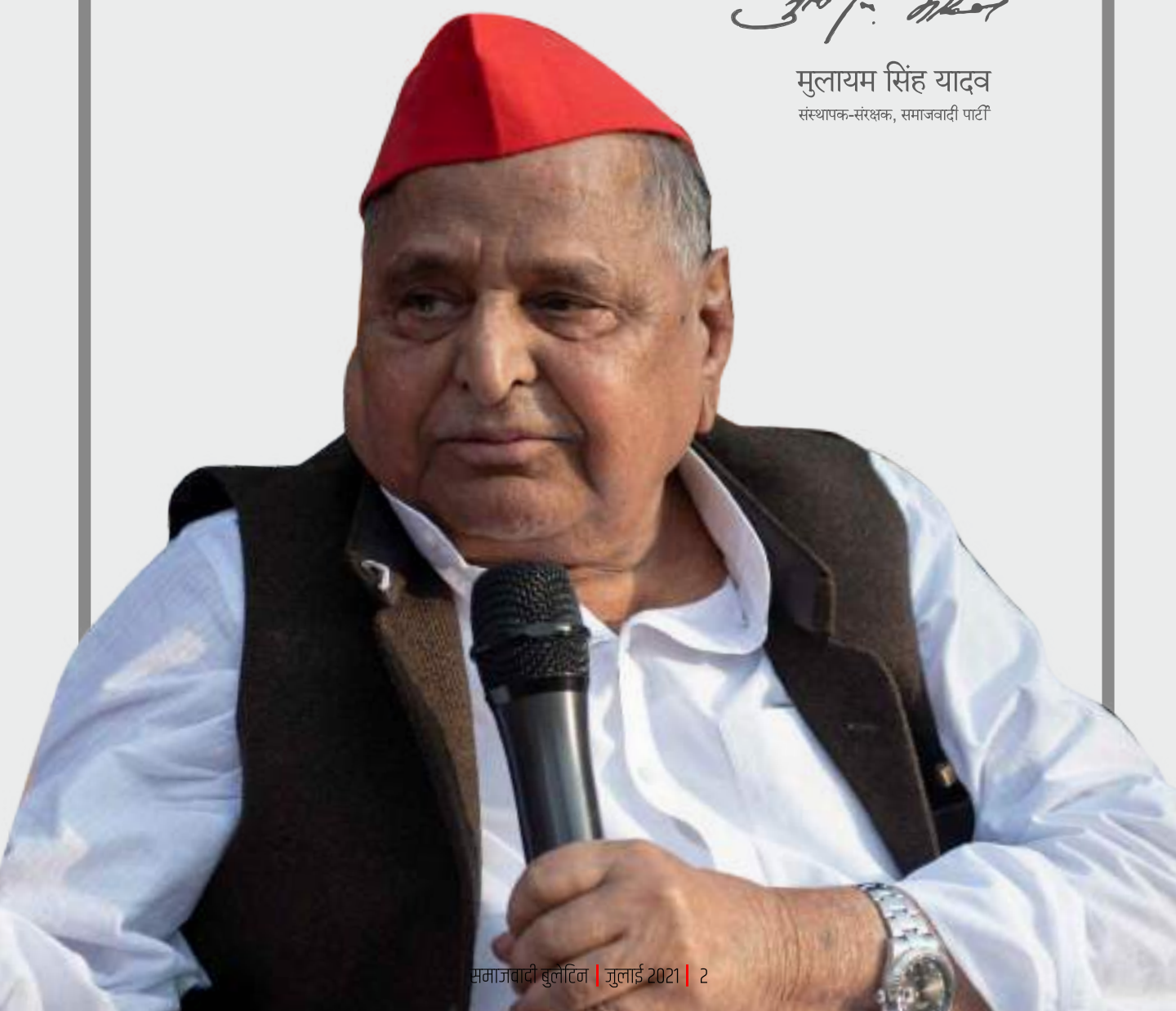

समाजवादी बुलेटिन

जुलाई 2021

वर्ष 22| संख्या 09

प्रिय पाठकों,
समाजवादी बुलेटिन आपकी अपनी पत्रिका है। इसके नए और बदले कलेवर को आप सबने सराहा है। आपका यह उत्साह वर्धन हमारी ऊर्जा है। कृपया अपनी राय से हमें अवगत कराते रहें। इसके लिए आप हमें नीचे दिए गए ईमेल पर लिख सकते हैं। कृपया अपना पूरा नाम, पता एवं मोबाइल नंबर जरूर दें। हम बुलेटिन को और बेहतर बनाने का प्रयास जारी रखेंगे। आपके संदेश की प्रतीक्षा रहेगी।
धन्यवाद

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक

प्रोफेसर रामगोपाल यादव

☎ 0522 - 2235454

samajwadibulletin19@gmail.com

bulletinsamajwadi@gmail.com

Mob:- 9598909095

/samajwadiparty

समाजवादी पार्टी के लिए

19, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ से प्रकाशित

आस्था प्रिंटर्स, गोमती नगर, लखनऊ से मुद्रित

R.N.I. No. 68832/97

अंदर

रोजगार के फर्जी दावे कर रही सरकार 39

16 कवर स्टोरी

जनमत पर डाका

क्रांति रथ पर अखिलेश उन्नाव से शंखनाद!

लक्ष्य 2022 08

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने 21 जुलाई 2021 को उन्नाव से भाजपा के खिलाफ शंखनाद किया। लखनऊ से क्रांति रथ पर सवार होकर उन्नाव पहुंचे श्री अखिलेश यादव का लखनऊ-कानपुर हाई-वे पर जगह-जगह भव्य स्वागत किया गया। स्वागत में सर्वत्र जोशीली भारी भीड़ थी।

अखिलेश ने चार सूत्रों में पिरोए समाजवादी सरोकार 30

मोदी राज: महंगाई मार गई! 41

आजम साहब के प्रति
भाजपा के रवैए पर बढ़ता जा रहा रोष

बुलेटिन ब्यूरो

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के संस्थापक सदस्य और लोकसभा सांसद मोहम्मद आजम खान के खिलाफ उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के दुर्भावनापूर्ण व्यवहार के खिलाफ रोष लगातार बढ़ता जा रहा है। अब यह और

स्पष्ट हो रहा है कि आजम खान साहब के खिलाफ भाजपा और यूपी की सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। इसी भावना के तहत उनके खिलाफ तमाम मुकदमे लादे गए हैं जिनका कोई आधार नहीं। उनके खिलाफ इसी द्वेषपूर्ण भावना के कारण आजम साहब अस्वस्थ भी हो गए हैं और उनका लगातार इलाज चल रहा है।

देश के सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने

श्री आजम खान देश प्रदेश के प्रतिष्ठित राजनेता हैं। वे 9 बार विधायक, 5 बार मंत्री और एक बार राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। इस समय वह रामपुर से लोकसभा के सदस्य हैं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय जैसा उच्च शैक्षणिक संस्थान उन्हीं की देन है।

आजम साहब के इलाज को लेकर अहम और राहत भरा निर्णय दिया है। मीडिया की खबरों के मुताबिक आजम खान साहब मेदांता अस्पताल में इलाज करा सकते हैं। उन्हें इलाज का सारा खर्च खुद वहन करना पड़ेगा।

यह आदेश आजम खान साहब की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सीतापुर के जेल अधीक्षक सुरेश सिंह ने मेदांता अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉ. राकेश कपूर को इस संबंध में पत्र भेजा है।

सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल प्रबंधन को निर्देश दिया है कि डॉक्टरों की टीम परिवार के सदस्यों से मिल सकती है। सीतापुर जेल अधीक्षक ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की सरकारी अधिवक्ता अजय विक्रम सिंह ने जानकारी दी। अदालत के आदेश को ही मेदांता अस्पताल को भेजा गया है।

सीतापुर कारागार में कोरोना की चपेट में आने बाद लखनऊ के मेदांता अस्पताल में उनका लंबा इलाज चला लेकिन उसके बाद जिस तरह उन्हें आनन फानन डिस्चार्ज किया गया पर उस पर सरकार केदबाब की भूमिका होने को लेकर सवाल भी उठे। उन सवालों में दम था इसकी पुष्टि तब हो गई जब उन्हें डिस्चार्ज होने के महज 1 सप्ताह के बाद तबियत बिगड़ने पर दोबारा लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा जहां उनका इलाज चल रहा है।

ज्ञातव्य है कि श्री आजम खान देश प्रदेश के प्रतिष्ठित राजनेता हैं। वे 9 बार विधायक, 5 बार मंत्री और एक बार राज्यसभा सदस्य रह

फाइल फोटो

आजम साहब के साथ घोर अन्याय कर रही भाजपा

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव श्री आजम खान के स्वास्थ्य के प्रति चिंता करते हुए दिल्ली में संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेकर 20 जुलाई को लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचते ही सीधे मेदांता अस्पताल गए। अस्पताल में भर्ती समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य और लोकसभा सांसद मोहम्मद आजम खान के स्वास्थ्य की जानकारी ली। उनके साथ राष्ट्रीय सचिव श्री राजेन्द्र चौधरी भी थे।

श्री अखिलेश यादव ने डाक्टरों से आजम साहब के बेहतर और जल्द इलाज के संदर्भ में परामर्श भी किया। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने आजम खान साहब के साथ घोर अन्याय किया है और उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। माननीय न्यायालय पर पूरा भरोसा है। न्यायालय से इंसाफ की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार असंवेदनशील है।

चुके हैं। इस समय वह रामपुर से लोकसभा के सदस्य हैं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय जैसा उच्च शैक्षणिक संस्थान उन्हीं की देन है।

ऐसी शख्सियत के खिलाफ सत्तारूढ़ पार्टी के कहने पर पुलिस-प्रशासन द्वारा की जा रही इस मनमानी कार्रवाई के खिलाफ समाजवादी पार्टी लगातार मुखर रही है। खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने गिरफ्तारी के मुद्दे पर लगातार सरकार को घेरा है।

कानूनी मामलों के जानकारों के मुताबिक चूंकि दर्ज 90 मामलों में से अब तक 86 मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है ऐसे में माना जा रहा है कि बाकी जमानत मिलते ही श्री आजम खान रिहा हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी उस घड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रही है। उल्लेखनीय है कि आजम साहब के साथ उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान भी जेल में हैं।

आजम खान साहब की रिहाई की मांग पर समाजवादी पार्टी लगातार मुखर होकर सड़क पर उतर रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के निर्देश पर दिनांक 15 जुलाई को हुए प्रदेश व्यापी प्रदर्शन कार्यक्रम में आजम खान साहब की रिहाई प्रमुख मांगों में शामिल थी।

कई जनपदों में पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए आजम साहब की रिहाई की मांग वाली तख्तियां पकड़े हुए थे।

खुद श्री अखिलेश यादव कई अवसरों पर यह आरोप लगा चुके हैं कि आजम साहब के खिलाफ राजनीतिक द्वेष के तहत कार्रवाई की जा रही है और उन्हें तत्काल रिहा किया

राजनीति का यह घिनौना स्वरूप

आजम खान साहब को अस्पताल से डिस्चार्ज करने और जेल भेजने को लेकर उनकी पत्नी व रामपुर की विधायक डॉ तंजीन फातिमा ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाया है।

रामपुर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं तो यही मानती हूं कि कोई षडयंत्र या साजिश है। यह भी राजनीति का एक घिनौना स्वरूप ही है, यकीनन सियासी रंजिशें ही हैं। जब उन्हें डिस्चार्ज किया गया था उस वक्त भी मैंने कहा था कि वो पूरी तरह से सेहतमंद नहीं हैं और पता नहीं ऐसे कौन से हालात थे कि उन्हें सेहतमंद बताकर अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था।

उन्होंने कहा कि जिस वक्त उन्हें डिस्चार्ज किया गया था, मैंने वीडियो देखा था वो व्हीलचेयर से ले जाए जा रहे थे और उनके हाथ पैर बेहद कमजोर थे और ठीक से उनसे एंबुलेंस में चढ़ा भी नहीं जा रहा था, उन्हें सहारा देखकर चढ़ाया गया था।

जाना चाहिए। श्री अखिलेश यादव ने आजम साहब के परिवारजनों के साथ लगातार संपर्क बना रखा है और कई अवसरों पर रामपुर जाकर उनसे मुलाकात भी की है।

सपा की ओर से 15 जुलाई को हुए प्रदर्शन के बाद भी कई जनपदों में पार्टी के कार्यकर्ता रिहाई की मांग करते हुए सड़क पर उतरे। मेरठ में कलेक्ट्रेट पर कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। बाद में राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा।

ज्ञापन में कहा गया है कि प्रदेश सरकार आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम खान को पूरी तरीके से स्वस्थ न होने के बावजूद जेल में यातनाएं दे रही थी, जिस कारण पूर्व सांसद का स्वास्थ फिर खराब हो गया। इस कोरोना काल में भाजपा सरकार की ओर से ऐसा कार्य करना यह दर्शाता है कि यह बदले की राजनीति कर रही है।

बदायूं में भी सपा नेताओं ने मुहिम छेड़ दी है। जिसके तहत सपा के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता कलक्ट्रेट पहुंचे। जहां उन्होंने नगर मजिस्ट्रेट के जरिए राज्यपाल को संबाेधित अपना ज्ञापन सौंपा। बागपत में श्री आजम खान की रिहाई को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। जिसमें आजम खान साहब की रिहाई की मांग की गई। सपा नेताओं ने कहा कि वरिष्ठ नेता आजम खान बीमार हैं। इसे देखते हुए उन्हें छूट दे देनी चाहिए, ताकि वह अपना इलाज सही तरीके से करा सकें। कोरोना पाजिटिव होने के बावजूद उनको रियायत नहीं दी गई, जबकि आजम खान सांसद भी हैं।

क्रांति रथ पर अखिलेश

उन्नाव से शंखनाद

बुलेटिन ब्यूरो

उत्तर प्रदेश में महज कुछ महीनों के बाद होनेवाले विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के पक्ष में लगातार बढ़ रहे जनसमर्थन के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने 21 जुलाई 2021 को उन्नाव से भाजपा के खिलाफ शंखनाद किया। लखनऊ से क्रांति रथ पर सवार होकर उन्नाव पहुंचे श्री अखिलेश यादव का लखनऊ-कानपुर हाई-वे पर जगह-जगह भव्य स्वागत किया गया। स्वागत में सर्वत्र जोशीली भारी भीड़ थी।

सरोजनीनगर, अमौसी एयरपोर्ट, दारोगा खेड़ा, बंथरा, बंथरा बाजार, कटी बगिया, बनी, नवाबगंज और उन्नाव में हर जगह श्री अखिलेश यादव का जय-जयकार के साथ फूल-मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। उन्नाव पुल के पास व्यापारियों ने स्वागत किया। यहां उन्हें दुर्गा माता की पूजी चुनरी भेंट की गई। सरौसी गांव में जहां मुख्य कार्यक्रम था वहां हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। लोगों ने उन पर फूल बरसाए, सारा माहौल अखिलेश यादव जिन्दाबाद के नारों से गूंजता रहा है।

श्री अखिलेश यादव ने उन्नाव के सरौसी गांव में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में इलाके के विख्यात जननेता रहे स्वर्गीय मनोहर लाल जी की 85वीं जयंती के अवसर पर मनोहर लाल इंटर कालेज में स्थापित स्वर्गीय मनोहर लाल की प्रतिमा का अनावरण किया एवं वहां एकत्र जन समुदाय को सम्बोधित किया। स्वर्गीय मनोहर लाल जी विधायक, सांसद तथा मंत्री रहे थे। श्री यादव ने कहा कि आज यहां बड़ी रैली होनी थी जिसकी प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है। जब कोविड खत्म होगा तो लाखो की रैली होगी।

उन्होंने स्वर्गीय मनोहर लाल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि जीवनभर वे गरीबों, दलितों, पिछड़ों की आवाज उठाते रहे और उनके लिए संघर्ष करते रहे। उनके संघर्ष की वजह से मुख्यधारा में खड़े नहीं होने वाले भी आगे आ पाए हैं। उन्होंने उनके पुत्र स्वर्गीय दीपक कुमार की पत्नी श्रीमती मनीषा दीपक के कोरोना से निधन पर दुःख जताते हुए सभी कोरोना पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि मनोहर लाल जी जीवनभर गरीबों, दलितों, पिछड़ों की आवाज उठाते रहे और उनके लिए संघर्ष करते रहे। उनके संघर्ष की वजह से मुख्यधारा में खड़े नहीं होने वाले भी आगे आ पाए हैं। उन्होंने उनके पुत्र स्वर्गीय दीपक कुमार की पत्नी श्रीमती मनीषा दीपक के कोरोना से निधन पर दुःख जताते हुए सभी कोरोना पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की।

श्री यादव ने कहा कि सन् 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए बहुत कम समय बचा है। भाजपा ने जनता को बुरी तरह निराश किया है। उसके वादे सपने बनकर रह गए हैं। अपने संकल्प-पत्र का एक भी वादा पूरा नहीं किया। किसान की आय दुगनी करने का वादा था, उल्टे किसानों की आय कम कर दी है। नौजवानों को रोजगार नहीं मिला। समाज के सभी वर्गो के लोग भाजपा सरकार को हटाना चाहते है।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने पंचायत चुनावों में नोट का इस्तेमाल किया और ब्लाक प्रमुख तथा जिला पंचायत अध्यक्षों के पद हथिया लिए। भाजपा ने सरकारी संस्थाओं को बेच दिया है। भाजपा सरकार के रहते नौजवानों की बेकारी बढ़ी, महंगाई बेलगाम हुई। साढ़े चार साल में एक फैक्ट्री प्रदेश में नहीं लगी है। लोगों को इस सरकार ने भुखमरी के कगार पर पहुंचा दिया है। प्रदेश में मंत्रिमण्डल विस्तार का कोई मतलब नहीं। यहां लोकतंत्र दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा भाजपा झूठी पार्टी है, इसे हटाइए। समाजवादी पार्टी इस बार 350 सीटें जीतेगी।

सच्चे समाजवादी थे स्व. मनोहर लाल : अखिलेश

फिर बुधवार को ही चुनावी सफर पर निकले अखिलेश

योगी सरकार पर बरसे पूर्व सीएम... बोले- हमने ट्रांसगंगा सिटी की नींव रखी, इस सरकार ने इसके किनारे लाशें बहा दीं

सत्ता में आए तो देंगे पक्का घर और मुफ्त बिज

'लकी उन्नाव' से अखिलेश ने फिर किया चुनावी रथयात्रा का श्रीगणेश

2022 में बाइसिकिल का संदेश लेकर निकले अखिलेश

घर और प्रतिष्ठान पहुंचे पूर्व सीएम, लिया सबका हालच

राष्ट्रीय अध्यक्ष का जोरदार स्वागत

बनी, नवाबगंज, दही चौकी, बाईपास पर डटे रहे सपा कार्यकर्ता

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के लखनऊ से उन्नाव तक की रथयात्रा के दौरान जगह-जगह उनका भव्य स्वागत हुआ। मीडिया में भी उनकी यात्रा की खबरें प्रमुखता से छाई रहीं। पेश है मीडिया में प्रकाशित सुर्ख़ियों की कुछ झलकियां।

श्री यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी जनता के बीच रहेगी। समाजवादी पार्टी भाजपा का विकल्प है। उन्होंने कहा कोरोना से मौतों के लिए सरकार की लापरवाही जिम्मेदार है। जनता को बहुत दुःख और परेशानियों का सामना करना पड़ा है। कोविड़ संक्रमितों को न बेड मिला, न इलाज और नहीं आक्सीजन मिली। उस समय भाजपा के लोग कहीं मदद में नहीं दिखाई दिए। केवल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ही राशन, दवा, ऑक्सीजन की मदद करने में सक्रिय रहे। समाजवादी सरकार ने जो 108 एम्बुलेंस चलाई थी वही मददगार बनी। अब तीसरी लहर की चर्चा है पर भाजपा सरकार इसके लिए क्या तैयारियां कर रही है, पता नहीं। उन्होंने उम्मीद जताई कि लोग समाजवादियों का काम देखेंगे। इस बार सभी भाजपा को हटाने में सहयोगी बनें क्योंकि भाजपा सरकार के रहते प्रदेश खुशहाल नहीं हो सकता है।

इस अवसर पर कार्यक्रम संयोजक श्री राम कुमार पूर्व विधायक, पूर्व सांसद अन्नू टंडन, विशम्भर प्रसाद निषाद एवं डाॅ अभिनव कुमार के साथ एमएलसी श्री सुनील यादव 'साजन', डाॅ राजपाल कश्यप, किरन पाल कश्यप, आनन्द भदौरिया, उदय राज यादव पूर्व विधायक, सुधीर रावत पूर्व मंत्री, कृपा शंकर पटेल पूर्व विधायक, धर्मेन्द्र यादव जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी उन्नाव की उपस्थिति उल्लेखनीय रही।

जनमत पर डाका

उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष एवं ब्लाक प्रमुख के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस-प्रशासन की मिलीभगत से जनमत पर डाका डाला। जिला पंचायत सदस्य एवं बीडीसी सदस्यों के चुनाव में जहां भाजपा को जनता ने नकार दिया था वहीं ब्लाक प्रमुख एवं जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में पार्टी ने सत्ता की ताकत का ऐसा नंगा व खुला खेल खेला जिसकी कोई मिसाल उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में नहीं है। जहां सदस्यों के चुनाव में जनता के वोट से हुए निर्णय में समाजवादी पार्टी ने भाजपा को कहीं पीछे छोड़ दिया था वहीं सदस्यों के जरिए हुए ब्लाक प्रमुख व जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भाजपा ने सारे नियम कायदे और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को शासन प्रशासन की मदद से रौंद डाला। खुलेआम गुंडागर्दी के सहारे भाजपा ने अपनी जीत का दावा तो किया है लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि सत्तारूढ़ भाजपा जनमत पर डाका भले डाल ले लेकिन जनता उसके साथ नहीं है। जनता समाजवादी पार्टी के साथ है एवं वह 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को सबक सिखाने और समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए तैयार बैठी है। पेश है **दुष्यंत कबीर** *की विस्तृत रिपोर्ट:*

लखीमपुर में पसगवां ब्लाक परिसर में नामांकन के दौरान सपा समर्थित महिला प्रत्याशी ऋतु सिंह और उनकी प्रस्तावक से पुलिस के सामने बदसलूकी की गई। ऋतु सिंह ने एसपी को तहरीर देते हुए कहा है कि वे जब नामांकन करने जा रही थीं तो भाजपा समर्थकों ने उन्हें और उनकी प्रस्तावक अनीता यादव को रोकते हुए उन दोनों की साड़ी खींची और दुर्व्यवहार किया। इस दौरान दोनों के कपड़े तक फट गए।

इटावा के बढ़पुरा ब्लाक में फायरिंग व पथराव की घटना के बाद एसपी सिटी का एक वीडियो सोशल मीडिया जमकर वायरल हुआ। जिसमें वह विभाग के आला अफसरों को मोबाइल पर बता रहे हैं कि सर मुझे भी थप्पड़ मारा है। भाजपा वाले बम लेकर आए हैं, पत्थर भी चलाए हैं।

सीतापुर के पहला ब्लॉक क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी के समर्थकों की गाड़ी से असलहा, लाठी-डंडे, ज्वलनशील पदार्थ बरामद हुए। सीतापुर में कमलापुर थाना क्षेत्र के कसमंडा ब्लॉक में नामांकन के दौरान जमकर बवाल हुआ। पर्चा दाखिल करने जा रहीं निर्दलीय उम्मीदवार को रोकने को लेकर हुए बवाल के दौरान हथगोले चले। कई राउंड फायरिंग हुई।

सिद्धार्थनगर के इटवा ब्लाक में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय के साथ दुर्व्यवहार कर उनकी गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया। कन्नौज एवं उन्नाव में चुनाव की कवरेज कर पत्रकारों को पीटा गया। रायबरेली के शिवगढ़ ब्लॉक परिसर के बाहर भाओजपा नेताओं ने जमकर हंगामा किया। सुल्तानपुर में मतदान के दौरान लंभुआ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उत्पात मचाया।

उपरोक्ता घटनाएं महज बानगी हैं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी के राज में हुए जिला पंचायत अध्यक्ष एवं ब्लाक प्रमुख के चुनावों की। इन चुनावों में पुलिस-प्रशासन को सत्तारूढ़ पार्टी ने अपने लठैतों की तरह इस्तेमाल कर जनमत पर डाका डालने का काम किया। सरकारी मशीनरी से जिला पंचायत अध्यक्ष एवं ब्लाक प्रमुख पदों पर जबरन कब्जा किया गया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उत्तर प्रदेश को भाजपा ने युद्ध भूमि में तब्दील कर दिया। यूपी की साख को खराब करने की जिम्मेदार भाजपा सरकार है।

इन चुनावों ने साफ कर दिया कि लोकतंत्र और संविधान में भाजपा की कोई आस्था नहीं है। भाजपा ने सत्ता का जैसा खुला दुरुपयोग किया है वह शर्मनाक है। लोकतंत्र की निर्ममता से हत्या की गई। चुनावों के दौरान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को नामांकन से जबरन रोका गया, मतदान के दौरान हिंसा हुई और प्रत्याशियों तथा समर्थकों का अपहरण तथा बंधक बनाने की घटनाएं हुईं।

चुनावों में बड़े पैमाने पर धांधली के बाद भी

आधी आबादी से बदसलूकी, चीरहरण काला धब्बा

बुलेटिन ब्यूरो

भाजपा सरकार में महिलाओं का सम्मान सुरक्षित नहीं है। ब्लाक प्रमुख चुनाव में आधी आबादी के साथ भाजपाइयों का बर्ताव घिनौना और निंदनीय है। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नामांकन केन्द्र में पहले से भाजपा के दर्जनों दबंग उपस्थित होकर निष्पक्ष चुनाव को खुली चुनौती देते रहे। लखीमपुर के पसगवां ब्लाक में नामांकन के समय समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती ऋतु सिंह एवं उनकी प्रस्तावक अनीता यादव के साथ दुर्व्यवहार किया गया और उनकी साड़ी खींची गयी। चीरहरण की यह घटना लोकतंत्र के इतिहास में काला अध्याय है।

ऋतु सिंह ने एसपी को दी गई तहरीर में कहा कि वे जब नामांकन करने जा रही थी तो भाजपा समर्थकों ने उन्हें और उनकी प्रस्तावक अनीता यादव को रोकते हुए उन दोनों की साड़ी खींची और दुर्व्यवहार

समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न जारी है। विभिन्न जनपदों में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं पर बड़े पैमाने पर फर्जी मुकदमें लगा दिए गए हैं। अज्ञात में तमाम लोगों को नामजद किया जा रहा है। समाजवादी कार्यकर्ताओं और नेताओं का अन्य तरीकों से भी उत्पीड़न किया जा रहा है। घरों में रात में दबिश डालकर परिवारीजनों से अभद्रता की जा रही है। पुलिस कार्रवाई में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता निर्मम पिटाई से घायल भी हुए हैं।

चिंताजनक बात यह है कि चुनावों में ऐसी धांधली तब हुई जबकि ऐसी आशंका जताते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त उत्तर प्रदेश को समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल द्वारा कई ज्ञापन दिए गए। इसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के रहते न तो भयमुक्त समाज बन सकता है और न ही निष्पक्ष चुनाव हो सकते हैं। राजभवन की भूमिका संवैधानिक दायित्व के निर्वहन के बजाय मूकदर्शक बने रहने की दिखाई देती है।

इसे देखते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा के प्रतिनिधिमंडल द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश को 13 जुलाई को ज्ञापन देकर एक ही जनपद में तीन वर्ष से अधिक समय से कार्यरत सहायक जिला निर्वाचन अधिकारियों (राजपत्रित अधिकारी) का स्थानांतरण कराने का आग्रह किया गया। ज्ञापन में कहा गया है कि आगामी विधानसभा निर्वाचन 2022 को निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से सम्पन्न कराने की दृष्टि से यह कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

ऐसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हालिया चुनावों में उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र को भाजपा ने बंधक बना लिया। प्रत्याशी के समर्थक क्षेत्र पंचायत सदस्यों को निर्वाचन प्रमाण-पत्र एवं मतदान के लिए पहचान पत्र होने के बाद भी वोट नहीं देने दिया गया वहीं दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी को गलत तरीके से फर्जी आईडी से मतदान कराया गया। उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन के अधिकारी सरकार के दरबारी की भूमिका निभाते रहे हैं

किया। इस दौरान दोनों के कपड़े तक फट गए। किसी तरह वह और प्रस्तावक वहां से बचकर नामांकन कक्ष में दाखिल हुईं और अपना पर्चा जमा किया। आरओ से नामांकन पत्र छीनकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उसे फाड़ दिया और उन्हें नामांकन नहीं करने दिया गया। जब उनका हाल जानने सपा के नेता मौके पर पहुंचे तो उन्हें बीच रास्ते में ही रोक कर भाजपा कार्यकर्ता हिंसा पर आमादा हो गए। पुलिस ने कोई मदद नहीं की।

सिद्धार्थनगर, इटवा में ब्लाक प्रमुख पद की समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती सूर्यमती पाण्डेय के साथ पुलिस की मौजूदगी में अभद्रता की गयी। कन्नौज के हसेरन ब्लाक में समाजवादी पार्टी की महिला प्रत्याशी को मारा-पीटा गया। बहराइच के शिवपुर ब्लाक में क्षेत्र पंचायत सदस्य यदुराई देवी के जेठ की हत्या कर दी गई। शिवपुर ब्लाक के भाजपा प्रत्याशी के पति ने रात में क्षेत्र पंचायत सदस्य यदुराई देवी के घर में घुस कर मारपीट किया। कुशीनगर के कसया ब्लाक में क्षेत्र पंचायत सदस्यों का उत्पीड़न किया गया। क्षेत्र पंचायत सदस्यों की दुकानें सील करते हुए परिजनों को जेल भेजा गया है।

और सत्ता के इशारे पर जबरन सहायक लगाये गये।

यह अजीब बात है कि जहां जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में ज्यादातर परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में आए थे और भाजपा की बुरी हार हुई थी वहीं जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में भाजपा सत्ता के बल पर धांधली करके बहुमत में आ गई है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में भाजपा के मुकाबले समाजवादी पार्टी के ज्यादा जिला पंचायत सदस्य व बीडीसी सदस्य जीते थे लेकिन भाजपा ने धन-बल, छल-बल और जिला प्रशासन के द्वारा जीते हुए जिला पंचायत सदस्यों व क्षेत्र पंचायत सदस्यों पर उत्पीड़न की कार्यवाही कर हारी बाजी

सपा के 19, भाजपा के 14 लेकिन प्रशासन ने हराया

सपा की दो महिला सदस्य बोलीं अपना ले जाने का प्रयास किया

मुझे थप्पड़ मारा है, बम लेकर आए हैं ये लोग..

सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में एसपी सिटी बयां करते दिखे अफसरों से अपना दर्द

मारपीट में चोट के निशाना दिखाते एसपी सिटी। अमर उजाला

Home » Uttar Pradesh » Lucknow » BJP Breaks The Reco

जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव: जीत के लिए भाजपा ने चला हर दांव, कई जगह हंगामा

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Updated Sat, 03 Jul 2021 08:50 PM IST

पंचायत चुनाव 2021

सपाइयों की पुलिस से झड़प, लाठीचार्ज

कलेक्ट्रेट के बाहर सपा कार्यकर्ताओं का हंगामा, प्रदर्शन

तथाकथित जीत में बदल कर अपने जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लाक प्रमुख बनवा लिए और लोकतंत्र की हत्या कर दी। जनता ने पंचायत चुनावों में भाजपा को हरा दिया तो उसने धांधली से अपनी खोई गरिमा हासिल करने का प्रयास किया। भय और लालच दिखाकर ब्लाक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों की कुर्सी हथियाने को अंजाम दिया गया।

सत्ता की भूख में भाजपा ने पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों को भी क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्यों पर प्रलोभन एवं आतंक के जरिए भाजपा के पक्ष में मतदान के लिए दबाव डाला। समाजवादी पार्टी के समर्थकों के मकान ध्वस्त किए गए। माफिया बताकर जिला बदर की कार्रवाई की गई। थाने पर बुलाकर प्रताड़ित किया गया। घरों पर दबिश डालकर परिवार की महिलाओं-बच्चों तक से अभद्रता की गई। ऐसा कर राजनीतिक एवं संवैधानिक मूल्यों की साख को बट्टा लगाया गया।

भाजपा सरकार की धांधली की शुरुआत नामांकन प्रक्रिया से ही शुरू हो गई थी। जिला पंचायत अध्यक्षों व ब्लाक प्रमुख के चुनाव में भाजपा ने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर कई जनपदों में समाजवादी पार्टी प्रत्याशियों को नामांकन तक नहीं करने दिया, कई जगह उनका अपहरण और बंधक बनाने का भी काम हुआ। भाजपाइयों को जबरन अध्यक्ष की कुर्सी दिलाई गई। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को एक मजाक बना दिया गया। सत्ता का ऐसा बदरंग चेहरा कभी नहीं देखा गया। ऐसा लग रहा था जैसे

जनादेश के अपहरण के किए भाजपा सरकार नंगा नाच करने पर उतारू है।

भाजपा ने लोकतंत्र को भारी क्षति पहुंचाई

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में भाजपा ने लोकतंत्र को भारी क्षति पहुंचाई है। भाजपा ने पहले जिला पंचायत अध्यक्ष और अब ब्लाक प्रमुख का चुनाव जीतने के लिए पूरे प्रदेश में नंगा नाच और खुली गुंडागर्दी की है। जिला प्रशासन और पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ता की तरह काम किया। निर्वाचन आयोग को जो भी काम करना था वह काम नहीं किया। चुनाव पर उसका नियंत्रण नहीं रहा।

उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में समाजवादी पार्टी के सदस्य बहुमत में जीते थे। लेकिन भाजपा सरकार ने सरकारी मशीनरी का दुरूपयोग करते हुए अध्यक्ष के पदों पर अपना कब्जा जमा लिया। भाजपा सरकार ने कई जनपदों में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के नामांकन पत्र नहीं दाखिल होने दिए, कई क्षेत्र पंचायत सदस्यों का अपहरण कर लिया गया और कइयों का पुलिस द्वारा उत्पीड़न कराया गया।

अपने को अनुशासित पार्टी होने का दावा करने वाली भाजपा के लोग इतने नीचे स्तर पर उतर आए कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने में भी लोकलाज नहीं रही। उन्होंने महिलाओं की इज्जत को तार-तार करने का पाप किया है। पूर्व स्पीकर श्री माता प्रसाद पाण्डेय को अपमानित किया गया।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतंत्र में इतने अन्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इन चुनावों में भाजपा ने डी.एम.-एस.पी. का उपयोग अपने राजनीतिक स्वार्थ साधन में किया है। भाजपा का नकाब उतर चुका है। किसान, नौजवान, व्यापारी, गरीब सभी तो भाजपा को हराना चाहते हैं। भाजपा का विकास से कोई मतलब नहीं है। समाजवादी पार्टी ही विकास के लिए प्रतिबद्ध है। भाजपा नफरत का एजेण्डा चलाती है। यह स्पष्ट हो चुका है, प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के साथ है। 2022 में भाजपा को उखाड़ने के लिए जनता संकल्पित है।

जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव में अपनी हार को जबरन छल कपट से जीत में बदल कर तात्कालिक रूप से मुख्यमंत्री और भाजपा नेतृत्व भले ही वाहवाही करा लें पर सच्चाई यह है कि भाजपा नेतृत्व में सत्ता का गुरूर छाया है, विपक्ष के प्रति द्वेष भाव है और अहंकार सिर पर चढ़कर बोल रहा है। भाजपा ने अपनी नीतियों से जनता को निराश कर दिया है। उत्तर प्रदेश में भाजपा का यही वास्तविक परिचय है।

लोकतंत्र में गरिमा जनादेश का सम्मान करने में होती है उसके साथ धोखाधड़ी करने में नहीं। कल विधानसभा के चुनाव में भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी। भाजपा ने जो धांधली चुनाव में की है उसका जवाब अब 2022 में जनता देने को तैयार बैठी है। समाजवादी पार्टी 2022 में विधानसभा की 350 सीटें जीतकर आएगी और भाजपा चंद सीटों पर सिमट कर विपक्ष में बैठने को मजबूर होगी। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर ही लोकतंत्र बहाल होगा और तभी जनता के साथ न्याय होगा क्योंकि समाजवादी पार्टी विकास और सद्भाव के लिए प्रतिबद्ध है। जनता समाजवादी पार्टी पर ही भरोसा करती है। उसका विश्वास है कि समाजवादी पार्टी ही उनकी समस्याओं का हल और राज्य का विकास कर सकती है।

चुनाव नहीं, जंगलराज !

सपा का जोरदार प्रदर्शन

कराया जनसमर्थन का एहसास

बुलेटिन ब्यूरो

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के निर्देशानुसार दिनांक 15 जुलाई 2021 को समाजवादी पार्टी ने ब्लाक प्रमुख एवं जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनावों में भाजपा सरकार द्वारा की गई धांधली, बेकाबू महंगाई और किसानों के मुद्दे समेत अन्य मांगों को लेकर प्रदेश के सभी तहसील मुख्यालयों पर जबरदस्त प्रदर्शन किया। राज्य भर में लाखों कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इस प्रदर्शन के जरिए किसानों को उपज का न्यूनतम मूल्य दिलाने, गन्ने का बकाया भुगतान, रोजगार दिलाने आदि की मांग से संबंधित राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन स्थानीय प्रशासन को सौंपा गया।

इन मांगों को लेकर सड़क पर उतरे समाजवादी

- किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य दिया जाए एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) की गारंटी दी जाए।
- प्रदेश में किसानों का गन्ने का बकाया भुगतान लगभग 15 हजार करोड़ रुपये तत्काल दिये जाएं।
- किसानों के ऊपर जो काले कृषि कानून थोपे जा रहे हैं उन्हें तत्काल वापस लिया जाए।
- बढ़ती महंगाई (डीजल-पेट्रोल, रसोई गैस, खाद, बीज, कीट नाशक दवाएं, कृषि यंत्र इत्यादि) पर रोक लगाई जाए।
- बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिया जाए।
- उत्तर प्रदेश में ध्वस्त कानून-व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए।
- महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों पर रोक लगाई जाए।
- समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खां और उनके परिवार व पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न बंद हो तथा उनके ऊपर फर्जी मुकदमें दर्ज करना तत्काल बंद किया जाए।
- उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार द्वारा किए जा रहे संगठित अपराधों को अविलंब बंद किया जाए।
- उत्तर प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को तत्काल दुरुस्त किया किया जाए।
- बढ़ते भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जाए।
- कोरोना काल में सरकार द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की जांच कराई जाए और मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिया जाए।
- जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में हुई धांधली एवं हिंसा की जांच कराई जाए। जांच में पाए गए दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और पुनः मतदान कराया जाए।
- पत्रकारों के ऊपर लगातार हो रहे हमले और हत्याओं पर रोक लगाई जाए।
- दलित वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग पर हो रहे अत्याचार बन्द हों।
- पिछड़े वर्ग को अनुमन्य 27 प्रतिशत आरक्षण में कटौती बन्द हो।

फोटो फीचर : प्रदर्शन, 15 जुलाई

लिस लखनऊ

तहसील सदर,हरदोई

अखिलेश ने चार सूत्रों में पिरोए समाजवादी सरोकार

संपर्क, संवाद, सहयोग और सहायता का आह्वान

फाइल फोटो

रविकान्त

सहायक प्रोफेसर, हिन्दी, लखनऊ विवि

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने एक जुलाई को जन्मदिन की बधाई स्वीकारते हुए अपने कार्यकर्ताओं को संपर्क, संवाद, सहयोग और सहायता का मंत्र दिया है। जनता की सेवा करने वाले इन सूत्रों की जरूरत हमेशा रहती है, लेकिन जब आपदा हो तो इन मूल्यों की जरूरत और ज्यादा बढ़ जाती है।

अखिलेश यादव के ये चार सूत्र इसलिए अहम हैं क्योंकि राजनीति सिर्फ सत्ता हासिल करने का जरिया नहीं है। राजनीति समाज को बेहतर करने का सबसे त्वरित माध्यम है। भारत जैसे विषमतामूलक समाज के लिए तो राजनीति ज्यादा कारगर माध्यम है लेकिन सवाल मूल्यों का है। राजनीति के केन्द्र में आम लोगों की चिंता मुख्य होनी चाहिए न कि सत्ता का सुख भोग। इसीलिए राजनीति में सबसे मूल्यवान है, सेवा और संवेदनशीलता।

सरकार और उसके तंत्र की असली परीक्षा कोरोना आपदा में हुई। कोरोना काल में सरकार की मंशा स्पष्ट रूप में सामने आ गई। सत्ताधारियों ने कोरोना संकट और लोगों की कोई परवाह नहीं की। संवेदनहीनता और कुप्रबंधन की पराकाष्ठा का यह उदाहरण है। इसके बरक्स तमाम पत्रकारों, विपक्षी दलों और संस्थाओं ने आगे बढ़कर लोगों की

मदद की। यूपी में समाजवादी पार्टी ने उल्लेखनीय काम किया। लॉकडाउन में सड़कों पर निकले लाखों मजदूरों को राशन पहुंचाने से लेकर एकमुश्त रकम की सहायता सपा की तरफ से की गई।

दूसरी लहर के दौरान भी सपा मुखिया और पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों ने बीमारों के इलाज खर्च से लेकर ऑक्सीजन, दवाइयां आदि का इंतजाम किया। दूसरी तरफ यूपी की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार ने आत्मनिर्भरता के छद्म का प्रचार करके भारत के करोड़ों लोगों को जीने-मरने के लिए छोड़ दिया था। इन स्थितियों में यूपी के विभिन्न क्षेत्रों में सपा की ओर से ढेरों इंतजाम किए गए। सपा ने इस काम कोई प्रचार नहीं किया। जहां सेवा का संकल्प हो, वहां शोर नहीं होना चाहिए।

एक कहावत है कि अगर आप दाएं हाथ से किसी को दान दे रहे हैं तो बाएं हाथ को भी खबर नहीं होनी चाहिए। इस भाव से ही सपा मुखिया ने अपनी पार्टी और कार्यकर्ताओं को लोगों की सेवा करने के लिए निर्देशित किया था। हालांकि सपा के सामने एक ऐसी प्रचार तंत्र वाली पार्टी सत्ता में है जिसके विज्ञापन अखबारों के पूरे पेज से लेकर टेलीविजन पर होने वाले अंतरालों में पटे होते हैं। ऐसे हालातों में सपा मुखिया द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को लोगों की सेवा करने के लिए दिया गया संकल्प प्रशंसनीय ही नहीं बल्कि प्रेरक भी है।

कोरोना से हुई मौतों और बदइंतजामी के कारण यूपी सरकार के प्रति लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। यूपी की जनता भाजपा सरकार से मुक्त होने के लिए छटपटा रही है। पंचायत चुनाव इसका प्रमाण है। लेकिन हार से बौखलाई योगी सरकार ने जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लाक प्रमुख चुनावों में पार्टी और प्रशासन दोनों ही स्तरों पर अराजकता और आतंक के माहौल में जनादेश का अपहरण कर लिया।

इसके बरक्स यही प्रशासन कोरोना आपदा में सोया हुआ था। संघ और भाजपा के कार्यकर्ता नदारत थे। सरकारी बदइंतजामी के कारण हजारों लोग काल कवलित हो गए। मीडिया मैनेजमेंट के सहारे सरकार अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश करती रही। गंगा में उतराती लाशों ने सरकार के झूठ को बेपर्दा कर दिया। अगले साल विधान सभा चुनाव होने हैं। योगी सरकार के पास जनता के बीच जाने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है। उसके रिपोर्ट कार्ड में केवल जनता की बदहाली और कराहें हैं।

अपने साढ़े चार साल के कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे

फाइल फोटो

फाइल फोटो

सार्वजनिक सेक्टर में कोई उल्लेखनीय काम नहीं किया। योगी आदित्यनाथ वैसे भी नाम बदलने के लिए मशहूर हैं। पिछली यानी अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं और कार्यक्रमों को नाम बदलकर अपना बनाने की कोशिश की गई लेकिन इस मद में ना तो कोई खास बजट दिया गया और न ही स्वास्थ्य सेवाओं और साधनों का विकास हुआ बल्कि गरीब मध्यवर्ग के हित की अनेक सेवाओं को बंद या कमजोर कर दिया गया। दरअसल, समाजवादी मूल्य जनहितकारी होते हैं, लेकिन आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर एलान कर दिया कि यूपी में समाजवाद नहीं चलेगा। यही कारण है कि आज गरीब और मध्यवर्ग बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, बीमारी और सरकारी नियमों की ठगी का शिकार है। पेट्रोल, डीजल, गैस से लेकर तेल, राशन और सब्जी, फल के दामों में आग लगी हुई है।

कोरोना संकट काल में खाने के सामान से लेकर दवाई तक की जमाखोरी और कालाबाजारी हुई लेकिन बड़े कारोबारियों की हितकारी योगी सरकार ने इन पर कोई कार्यवाही नहीं की। डा. राम मनोहर लोहिया इस बात को जानते थे कि पूंजीपति आपदा में भी गरीबों का शोषण करेंगे। इसलिए वे दाम बांधो नीति को लागू करने की बात करते थे लेकिन अंबानी, अडानी की पोषक यह सरकार गांव गिरांव में रहने वाले मजदूर-किसान-दस्तकार की चिंता नहीं करती। सच्चाई यह है कि भाजपा सरकार बड़ी बेरहम और निर्लज्ज है।

यूपी सरकार की जिम्मेदारी तय करने के बजाय मूल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए सांप्रदायिक मुद्दों को उछाला जा रहा है। आखिर भाजपा कब तक धर्म के नाम पर लोगों की भावनाओं से खेलती रहेगी? हाल ही में अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर के चंदे में घोटाले के आरोप लग रहे हैं। हिन्दू धर्म और राम के प्रति इनकी न कोई आस्था है और न कोई प्रतिबद्धता। ये महज सत्ता के लालची लोग हैं, जो नफरत फैलाकर विभाजनकारी राजनीति कर रहे हैं। इससे देश की सुख शांति भंग हो रही है। बढ़ती असहिष्णुता और धर्मांधता के कारण दुनिया में भारत की बदनामी हो रही है।

समाजवादी पार्टी लगातार सरकार को आईना दिखाती रही है। यूपी में प्रशासनिक असफलता और कोरोना काल में सरकारी बदइंतजामी को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार सवाल करती रही है लेकिन सरकार गूंगी और बहरी बनकर बैठी है। इसका कारण योगी आदित्यनाथ का तानाशाहीपूर्ण रवैया है। वे प्रदेश को मठाधीशी अंदाज में चला रहे हैं। उन्होंने 4 साल में न तो अपनी पार्टी के नेताओं और विधायकों को खास तवज्जो दी और न ही जनता के सरोकारों को। योगी पहले मुख्यमंत्री हैं जिनके खिलाफ सत्तादल के 100 से अधिक विधायक विधानसभा में धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। कुछ भाजपा विधायक और मंत्री कैमरे पर योगी की तानाशाही की आलोचना कर चुके हैं। हालिया मोदी बनाम योगी के घटनाक्रम में करीब 250 विधायकों ने योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली पर सवाल उठाते

हुए आलाकमान से अपनी नाराजगी जाहिर की है।

यूपी में विधायक और मंत्रियों की कोई हैसियत नहीं है। यहां सरकार की पोल खोलने वालों की खैर नहीं है। यूपी में माफिया और गुंडाराज चरम पर है। शराब माफिया के खिलाफ खबर करने वाले एबीपी के पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की संदिग्ध परिस्थियों में प्रतापगढ़ में हुई मौत गहरे सवाल खड़े करती है। पिछले चार साल में सरकार और माफिया ठेकेदारों की मिलीभगत से यूपी की जनता बहुत प्रताड़ित हो रही है लेकिन इस गठजोड़ का खुलासा करने वालों पर ही सरकार चाबुक चलाती है।

यूपी में सबसे बड़े विपक्षी दल के रूप में समाजवादी पार्टी है। सपा मुखिया अखिलेश यादव नौजवान हैं। गोदी मीडिया में सपा की कथित निष्क्रियता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वास्तव में, यह मीडिया द्वारा प्रायोजित एक प्रोपेगेंडा है। सपा नौजवानों की पार्टी है। नागरिकता विरोधी कानून और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सपा के नौजवान कार्यकर्ता लगातार आंदोलन करते रहे हैं। किसान आंदोलन के समर्थन में गांव -कस्बों में होने वाले सपा के अभियान में इन नौजवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। उन्होंने लाठियां खाईं और जेल गए लेकिन किसी अखबार और चैनल ने सपा की इन गतिविधियों को प्रमुखता से जगह नहीं दी लेकिन, सोशल मीडिया पर जूझते इन नौजवानों के वीडियो और तस्वीरों से उनके जुझारूपन और सक्रियता को देखा जा सकता है।

पुलिस-प्रशासन से टकराते इन जोशीले नौजवान कार्यकर्ताओं को समय-समय पर पार्टी का दिशा निर्देश और पुराने समाजवादी क्षत्रपों का सहयोग मिलना जरूरी है। ताकि इस ऊर्जा का सही इस्तेमाल किया जा सके। इस सिलसिले में कोरोना की दूसरी लहर से पहले कई मंडलों में

सपा नौजवानों की पार्टी है। सपा के नौजवान कार्यकर्ता लगातार आंदोलन करते रहे हैं। किसान आंदोलन के समर्थन में गांव -कस्बों में होने वाले सपा के अभियान में इन नौजवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है।

समाजवादी प्रशिक्षण शिविर एवं उसमें हिस्सा लेने के लिए सपा मुखिया अखिलेश यादव के दौरों क खासा प्रभाव रहा। सपा की धमनियों में नौजवानों का रक्त बहता है। इसे पार्टी भी समझती है। सपा अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं को रचनात्मक राजनीति के लिए प्रेरित कर रहे हैं। लोगों से संपर्क करके संवाद कायम करना जरूरी है। इससे लोगों के दुख दर्द को बांटा जा सकता है। इस प्रक्रिया में संवेदनशीलता पैदा होती है। संवेदनशीलता लोगों का सहयोग करने के लिए प्रेरित करती है। इससे जनमानस में पार्टी के प्रति लगाव पैदा होता है। इसलिए जनता के बीच जाना बेहद जरूरी है।

तमाम राजनीतिक विश्लेषकों की राय में समाजवादी पार्टी भाजपा से मुकाबला करने में सबसे ज्यादा सक्षम है। उसके पास संगठन है। नौजवान कार्यकर्ताओं का बड़ा हुजूम है। स्थानीय अनुभवी क्षत्रप हैं। सोने पर सुहागा, अखिलेश यादव की साफ-सुथरी और विकास करने वाली छवि है। सपा अध्यक्ष की यह छवि पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में स्वास्थ्य, पुलिस प्रशासन, नौजवानों की शिक्षा और गरीबों को पेंशन जैसे उल्लेखनीय काम किए थे। साथ ही लखनऊ में इकाना अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस वे, लखनऊ मेट्रो उनके कार्यकाल के चमकदार सितारे हैं। कानपुर, आगरा जैसे शहरों में मट्रो प्रोजेक्ट शुरू किए गए। सपा सरकार में गांव में पुलों और सड़कों का भी बहुत निर्माण हुआ।

मूल रूप से किसानों की पार्टी मानी जाने वाली सपा किसानों के मुद्दों पर हमेशा संजीदा रहती है। किसान आंदोलन में सपा के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। स्वयं अखिलेश यादव प्रदर्शन करते हुए लखनऊ में गिरफ्तार हुए। वे पश्चिमी यूपी में राष्ट्रीय लोकदल के वर्तमान अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ किसान पंचायतों में शामिल हुए हैं। इसे लगातार गतिशील रखने के लिए संगठन को अधिक समावेशी बनाते हुए बूथों पर नौजवानों की टीमें तैनात करनी होगीं व सामाजिक समीकरण बेहतर करते हुए सबकी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी।

(यह लेखक के अपने विचार हैं)

अखिलेश जी का जन्मदिन
परिवर्तन का संकल्प

बुलेटिन ब्यूरो

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के जन्मदिन पर एक जुलाई 2021 को पूरे प्रदेश में विविध प्रकार के आयोजन हुए। श्री अखिलेश यादव का जन्मदिन उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों की जनता, विभिन्न सामाजिक संगठनों, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हर्षोल्लास से मनाया। सपा के कार्यकर्ताओं एवं भाजपा सरकार में पीड़ित शिक्षामित्रों, अन्य विभागों के कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने सन् 2022 में परिवर्तन का संकल्प लेते हुए समाजवादी पार्टी की सरकार बनने का भरोसा दिया।

श्री अखिलेश यादव ने उनके जन्म दिवस पर लोगों ने जो स्नेह प्रदर्शित किया उससे अभिभूत होकर सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि अभी हमारे सामने कई चुनौतियां है और बहुत कुछ करना है। हमारे सामने एक बहुत चतुर किस्म का दल है। वह झूठे वादे करता है। नफरत फैलाता है और

समाज को बांटता है। आज जनता ने जो आशीर्वाद दिया है उससे हम सबके हौसले बुलन्द हुए हैं और नई ऊर्जा मिली है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि राज्य की जनता परिवर्तन चाहती है।

श्री अखिलेश यादव के जन्म दिन पर प्रदेश के तमाम जनपदों में अनेक स्थानों पर केक काटा गया, मिष्ठान्न वितरण के साथ गरीबों को अन्नदान तथा भोजन वितरण किया गया। कई स्थानों पर सुन्दर काण्ड का पाठ किया गया। वृक्षारोपण भी हुआ। कुछ ने श्री यादव को जहां कपूर, रुद्राक्ष के वृक्ष भेंट किए।

प्रदेश कार्यालय लखनऊ में नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद श्री अहमद हसन, राष्ट्रीय सचिव श्री राजेन्द्र चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेश उत्तम पटेल तथा श्री अरविन्द कुमार सिंह एमएलसी रामवृक्ष यादव द्वारा केक काटकर जन्मदिन मनाया गया। प्रातः से ही समाजवादी पार्टी कार्यालय, लखनऊ में हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सुप्रसिद्ध कवि पूर्व सांसद उदय प्रताप सिंह जी की का साइकिल गीत की प्रस्तुति स्क्रीन पर की गई।

कोने-कोने से आए गांवों के किसानों से लेकर प्रोफेसर, स्कूली बच्चों, वकील, नौजवान, विधायक, सांसद, पार्टी पदाधिकारी, महिलाएं, व्यापारी आदि सभी ने लोकप्रिय नेता श्री यादव को जन्मदिन की बधाई दी। उन्हें बधाई देने वालों में अन्य दलों के नेता एवं विधायक भी शामिल थे। श्री अखिलेश यादव ने कार्यालय में देर तक उपस्थित रहकर कार्यकर्ताओं से भेंट की और सभी का आभार व्यक्त किया।

समाज पर भारी भाजपा राज में बढ़ती बेरोजगारी

फोटो सौजन्य : गूगल

हुसैन रिज़वी
टीवी एंकर, वरिष्ठ पत्रकार

मोदी सरकार में नोटबंदी, जीएसटी और महामारी के बाद अर्थव्यवस्था पटरी से उतरती चली गई गयी और नतीजे के तौर पर देश को मिली है बेरोजगारी की विकराल समस्या। हर साल देश में एक करोड़ बेरोजगार लोगों के जुड़ने की चुनौती रही है लेकिन अब रोज़गार छिन जाने की चुनौती भी सामने है। बेरोजगार होने की रफ्तार तेज हो चुकी है और यही हाल रहा तो देश की बड़ी आबादी के हाथ में खरीदने के लिए रकम नहीं होगी। क्या भारत इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है?

यह बात चौंकाने वाली है मगर सच है कि महामारी के वक्त जब अर्थव्यवस्था की रफ्तार 7.3 फीसदी नकारात्मक रही थी तब भी देश के दौलतमंदों की दौलत 35 फीसदी बढ़ गयी। बेरोजगारी ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बीते साल महामारी के बीच अप्रैल और मई में बेरोजगारी की दर 23.5 और अप्रैल-जून तक 20.9 फीसदी तक पहुंच गई थी। 2021 में मई के महीने में बेरोजगारी दर 14.7 फीसदी के स्तर पर जा पहुंची। हालांकि जून में इसमें थोड़ा सुधार आया। फिर भी ये 9.19 प्रतिशत के स्तर पर बनी हुई है।

वैश्विक स्तर पर भारत था बेहतर, मगर अब नहीं

बीते 10 साल में वैश्विक बेरोजगारी की

औसत दर भारत में बेरोजगारी की दर के आसपास रही थी, मगर भारत इस औसत से थोड़ा बेहतर स्थिति में रहा था। यह बेहतरी अब खत्म हो चुकी है। 2020 में जहां वैश्विक बेरोजगारी 5.42 फीसदी थी, भारत में बेरोजगारी की सालाना दर 7.11 फीसदी पहुंच गयी। 2021 के आंकड़े बता रहे हैं कि हालात और भी बदतर होते जा रहे हैं। नीचे तालिका पर नज़र डालें तो स्थिति स्पष्ट होती है।

मोदी राज में बेरोजगारी दर :

दुनिया बनाम भारत

साल	दुनिया	भारत
2014	5.63	5.61
2015	5.64	5.57
2016	5.67	5.51
2017	5.57	5.42
2018	5.39	5.33
2019	5.4	5.36
2020	5.42	7.11

मोदी राज से पूर्व बेरोजगारी :

दुनिया बनाम भारत

साल	दुनिया	भारत
2010	5.92	5.64
2011	5.8	5.64
2012	5.77	5.65
2013	5.77	5.67

स्रोत- @statisa 2021

महामारी के पहले से ही बेरोजगारी का खौफ

महामारी के पहले से ही बेरोजगारी का खौफ

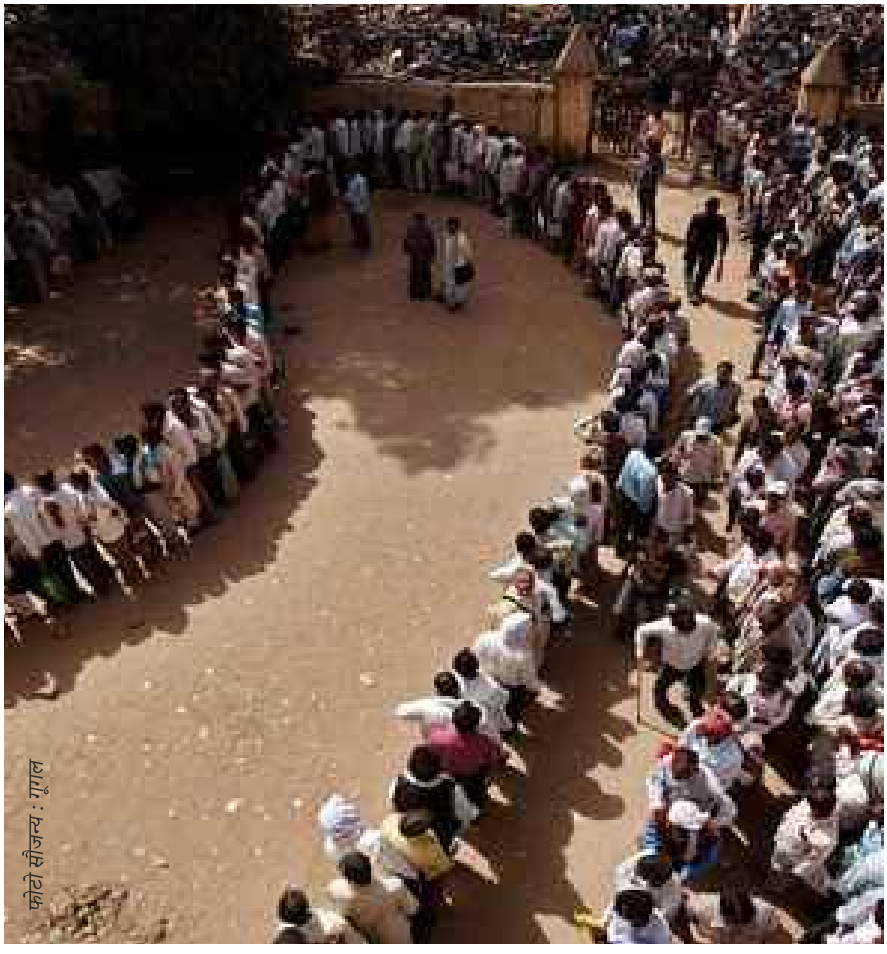

फोटो सौजन्य : गूगल

दिखने लगा था। साल दर साल गंभीर होती बेरोजगारी को समझना हो तो यह आंकड़ा महत्वपूर्ण है-

वर्ष	बेरोजगारी दर
मार्च 2016	8.7%
मार्च 2017	4.7%
मार्च 2018	6%
मार्च 2019	6.7%

2019 में अप्रैल से जून के बीच बेरोजगारी की दर 8.9 फीसदी पहुंच गई थी। जबकि, महामारी से ठीक पहले के तीन महीने जनवरी-मार्च 2020 में बेरोजगारी की दर 9.1 थी। जुलाई 2020 से जून 2021 तक 12 महीनों में औसत बेरोजगारी की दर 7.83 है। बेरोजगारी की दर मई 2021 में 11.9 फीसदी पहुंच गयी थी और यह लगातार बढ़ रही है।

जी-20 में भारत 5वें नंबर पर

जी-20 के देशों में भारत से बुरी स्थिति में केवल चार देश हैं- दक्षिण अफ्रीका जहां मार्च 2021 में सबसे ज्यादा 32.6 फीसदी बेरोजगारी है। उसके बाद स्पेन का नंबर आता है जहां 15.98 फीसदी बेरोजगारी है और तब ब्राजील और तुर्की हैं जहां अप्रैल 2021 में क्रमश: 14.7 और 13.9 फीसदी बेरोजगारी रही। मई 2021 में भारत 11.9 फीसदी बेरोजगारी के साथ पांचवें नंबर पर है।

पाकिस्तान, बांग्लादेश भी हैं भारत से बेहतर

एशियाई देशों में अधिकतम बेरोजगारी के मामले में भारत 7वें नंबर पर है। पाकिस्तान

(4.4%), भूटान (5%), बांग्लादेश (5.3%), श्रीलंका (5.2%) इंडोनेशिया (6.26), बांग्लादेश (4.2%) समेत तमाम देश भारत से बेहतर हैं। बेरोजगारी में भारत से बदतर एशियाई देश हैं- फिलीस्तीन (27.8%), जॉर्डन (25%), जॉर्जिया (18.5%), अर्मीनिया (17%), इराक (13.4%) और यमन (13.42%). (आंकड़े tradingeconomics.com)

महामारी के बाद बेकाबू हुए हालात

कोरोना महामारी निश्चित रूप से बड़ा संकट लेकर आयी। बेरोजगारी की रफ्तार अचानक बहुत तेज हो गयी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी सीएमआईई के मुताबिक 2021 में मई लगातार चौथा महीना था जब रोजगार में कमी आयी यानी बेरोजगारी बढ़ी। इन चार महीनों में 2 करोड़ 53 लाख लोगों की नौकरी चली गयी। जनवरी में जहां 40 करोड़ 7 लाख लोग रोजगार में थे। वहीं मई के अंत में यह संख्या घटकर 37 करोड़ 55 लाख रह गयी। जून में भी रोजगार में कमी का सिलसिला जारी रहा।

हालात कितने भयावह है इसे समझने के लिए सेंटर ऑफ सस्टेनेबल इम्पलॉयमेंट, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के संतोष मेहरोत्रा और जजाति के परिदा के शोध पत्र के आंकड़ों पर गौर करें। इसमें कहा गया है कि 2011-2012 और 2017-2018 के दौरान यानी 6 साल में 90 लाख लोगों ने नौकरियां गंवाई थीं। जाहिर है बीते चार महीने में जितनी नौकरियां गई हैं वह बीते छह साल में छूटी नौकरियों का ढाई गुणा है।

2011-12 से 2017-18 के बीच 90 लाख नौकरियां गईं

फोटो सौजन्य : गूगल

महामारी में बेरोजगारी की समस्या और भी विकराल हुई है लेकिन वास्तव में यह मोदी राज में लगातार गंभीर होती चली गयी है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का शोध पत्र

रोजगार की उम्मीद के बदले बेरोजगारी की ऐसी भयानक तस्वीर अच्छे दिनों की तो कतई नहीं हो सकती। अर्थव्यवस्था के पहिए की रफ्तार तेज करके ही बेरोजगारी की रफ्तार पर ब्रेक लगायी जा सकती है।

इसकी पुष्टि करता है। इसके मुताबिक 2011-12 और 2017-18 के बीच कृषि क्षेत्र में तेजी से लोगों ने रोजगार गंवाए। प्रति वर्ष 45 लाख दर से कुल 2 करोड़ 7 लाख लोग कृषि से दूर हुए। इस दौरान कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में लोगों की भागीदारी 49 फीसदी से घटकर 44 फीसदी रह गयी। इसी दौरान 35 लाख लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में रोजगार गंवाए। मैन्युफैक्चरिंग में 12.6 फीसदी से गिरकर रोजगार 12.1 फीसदी रह गया। नॉन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जहां 2004-05 में हर साल 40 लाख रोजगार पैदा हो रहे थे वहीं 2011-12 और 2017-18 के दौरान सिर्फ 6 लाख लोगों को रोजगार मिले।

चिंताजनक है श्रम बल में लगातार कमी

भारत में बेरोजगारी को एक समस्या के तौर पर समझना है तो हमें रोजगार के सेक्टर और पूरे श्रम बल भागीदारी की स्थिति को भी समझना होगा। 2020 में भारत में कुल कामगारों की संख्या 50.1 करोड़ थी। इनमें से 41.19 फीसदी कृषि क्षेत्र में काम कर रहे थे तो औद्योगिक क्षेत्र में 26.18 फीसदी और सेवा के क्षेत्र में 32.33 प्रतिशत कामगार लगे हुए थे।

उद्योग में श्रम बल की भागीदारी लगातार कम होती जा रही है। यह गंभीर चिंता का विषय है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने सत्ता संभाली थी तब श्रम बल की भागीदारी 52.5 फीसदी थी। 2016 में यह 50.4 फीसदी और फिर 2018 में 49.8 फीसदी के स्तर पर जा पहुंची।

सीएमआईई के मुताबिक 2019-20 में

श्रम बल की भागीदारी 42.7 प्रतिशत रह गयी थी। अप्रैल-मई 2021 में यह 40 फीसदी के स्तर पर आ गयी। यह 40 फीसदी तक पहुंचने के बाद और भी गिरकर 39.7 फीसदी हो चुकी है। ताजा श्रम बाजार सूचकांक बताता है कि रोजगार की दर मई 2021 में 35.3 फीसदी से गिरकर 6 जून 2021 तक 34.6 फीसदी हो चुकी है। अप्रैल-मई 2020 के बाद से रोजगार में श्रमिकों की भागीदारी अपने सबसे बुरे दौर में है।

नाकाफी रहे रोजगार सृजन के प्रयास

मोदी सरकार की योजनाओं से रोजगार सृजन की संख्या बहुत मामूली रही। न सिर्फ साल में एक करोड़ बेरोजगारों की खड़ी होती फौज के मुकाबले यह संख्या बेहद कम थी, बल्कि छूटते रोजगार की वजह से विकराल होती रही स्थिति को थामने में भी ये रोजगार समर्थ नहीं हो सकते थे। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत 2016-17 से लेकर 2020-21 के बीच चार साल में 21 लाख 71 हजार लोगों को रोजगार मिले तो 5 साल में पंडित दीन दयाल ग्रामीण कौशल योजना के जरिए 5 लाख 49 हजार लोगों को नौकरियां मिलीं।

दीन दयाल अंत्योदय योजना से 5 साल में 5 लाख 14 हजार 998 लोगों को काम मिला। जाहिर है पांच साल में पांच करोड़ नौकरियां होती तभी स्थिति संभल सकती थीं। लेकिन, ऐसा नहीं हुआ।

2 करोड़ सालाना रोजगार की उम्मीद के बदले बेरोजगारी की ऐसी भयानक तस्वीर अच्छे दिनों की तो कतई नहीं हो सकती।

अर्थव्यवस्था के पहिए की रफ्तार तेज करके ही बेरोजगारी की रफ्तार पर ब्रेक लगायी जा सकती है। आर्थिक विकास और बेरोजगारी के बीच व्युत्क्रमानुपाती (उल्टा) संबंध है। बंद हुए कारोबार को जिंदा करना, छोटे-मझोले उद्योगों को दोबारा खड़ा करना और समग्रता में कारोबार के लिए माहौल बनाना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।

इसके लिए पूंजी निवेश के प्रवाह सही किए जाने की सख़्त ज़रूरत है। औद्योगिक और कृषि विकास में तालमेल जरूरी है। बेरोजगारी की वजह से हताश और निराश श्रमबल यानी बेरोजगारों को तत्काल आर्थिक मदद की भी जरूरत है ताकि महामारी के दौर में उन्हें बचाया जा सके।

(यह लेखक के अपने विचार हैं)

रोजगार के फर्जी दावे कर रही सरकार

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा की अदूरदर्शी नीतियों के कारण बेरोजगारी ने भी अपना विकराल रूप दिखाया है। इस दुर्गति की दोषी है अर्थव्यवस्था विनाशक भाजपा सरकार। इस बेकारी ने जहां हजारों युवाओं का भविष्य अंधेरा कर दिया है वहीं हर साल लाखों नौकरियां देने के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के दावे का झूठ भी सामने ला दिया है।

हर साल लाखों को रोजगार का दावा करते भाजपा सरकार ते मुख्यमंत्री थकते नहीं परन्तु सच्चाई यह है कि शिक्षकों की भर्ती हो या डॉक्टरों की अथवा विभागीय रिक्तियों की हर जगह रुकावट दिखती हैं। वर्ष 2016 में समाजवादी सरकार में दारोगा भर्ती निकली थी, चयन हुआ और प्रशिक्षण भी दिलाया गया लेकिन अभी तक उनको न तो ज्वाइनिंग मिली हैं और नहीं उनको सैलरी मिली है।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने इसी तरह इन्वेस्टमेंट मीट का खूब प्रचार किया नए रोजगार के दावे किए गए, पर जमीन पर एक भी उद्योग नहीं लगा। नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट में यूपी का प्रदर्शन हर क्षेत्र में निचले पायदान पर दिखाया गया है।

बेरोजगारी के आंकड़े दिल दहलाने वाले हैं। अप्रैल 2020 में 12 करोड़ से अधिक लोगों की नौकरी गई। 30 मई को समाप्त सप्ताह में बेकारी दर 17.88 फीसदी पर पहुंच गई। शहरी बेरोजगारी में 10.8 फीसदी वृद्धि हुई। कोरोना काल में लॉकडाउन में कई कंपनियां बंद रही। जिनकी नौकरियां छूट गई हैं उन्हें दोबारा मुश्किल से रोजगार मिलेगा।

मोदी राज
महंगाई मार गई!

प्रेम कुमार
वरिष्ठ पत्रकार

पहले की महंगाई और अब की महंगाई में बड़ा फर्क आ चुका है। पहले गृहिणी सोचा करती थी कि उसके पति तो खूब कमा रहे हैं लेकिन ये महंगाई है जो उसे खा-पचा ले रही है। फिल्म *पीपली लाइव* में यह भावना खुलकर व्यक्त हुई थी और गीत के ये बोल बहुत प्रचलित हुए थे- **सखी सैयां तो खूब ही कमात है/महंगाई डायन खाय जात है...**

अब सैयां की कमाई पर ही आफत है। रोजगार छिन गये हैं। वेतन में कटौती हो चुकी है। कुछ रकम आई भी तो मानो महंगाई के गरम तवे पर बूंद-सी उड़ जाती है। एक तो सैयां की आमदनी घटी और दूसरा खर्चा दोगुना, तिगुना नहीं कई गुणा बढ़ गया। महंगाई की जानलेवा शक्ति किसी तमाम भयावहता को पीछे छोड़ चुकी है।

दोहरा संकट : महंगाई बढ़ी, नौकरियां गईं

जब तक हम महंगाई को रोजगार की कमी से नहीं जोड़ते, इसकी मारक क्षमता नहीं आंक सकते। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के सर्वे से पता चलता है कि अप्रैल-मई 2020 में जिन 10 करोड़ लोगों की नौकरियां गयीं, उनमें से डेढ़ करोड़ लोग 2020 के अंत तक बेरोजगार ही रह गये। अक्टूबर 2020 में चार सदस्यों वाले एक परिवार की मासिक

आमदनी 4,979 रुपये रह गयी थी जो जनवरी 2020 में 5,989 रुपये थी।

जिनकी नौकरी गयी वो परेशान हैं लेकिन जिनकी नौकरी कहने को बची हुई है वो अधिक परेशान हैं। सबसे भयावह आंकड़ा तो यह है कि देश में प्रतिदिन न्यूनतम 375 रुपये से कम आमदनी वाले लोगों की तादाद में 23 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। ये 23 करोड़ लोग नौकरी के बावजूद भूखे हैं क्योंकि महंगाई इन्हें जीने नहीं दे रही।

दैनिक भोगी कर्मचारियों की मासिक आमदनी 2019 में 9,135 रुपये थी जो 2020 में 7,965 रुपये रह गयी। स्थायी, अस्थायी और स्वरोजगार से जुड़े लोगों की औसत मासिक आमदनी 2019 में जहां 15,210 रुपये थी, वह 2020 में 12,625 रुपये मासिक रह गयी। कोरोना की दूसरी लहर के बाद 2021 में स्थिति और भी खराब होती चली जा रही है। जब जेब में रकम नहीं हो, तो महंगाई से मुकाबला कैसे किया जाए। लिहाजा महंगाई किचन में असर दिखाती हुई पेट में चूहे की तरह उत्पात कर रही है।

थोक मूल्य सूचकांक (डबल्यूपीआई) मई 2021 में 12.96 प्रतिशत की ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गयी। जनवरी में यही आंकड़ा महज 2.03 फीसदी था। थोक मूल्य सूचकांक में बढ़ोतरी का मतलब खुदरा बाज़ार में उछाल होता है। यही उछाल आम लोगों की कमर तोड़ देता है। आने वाले समय में थोक मूल्य सूचकांक में और बढ़ोतरी होने की आशंका हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है पेट्रोल-डीजल की कीमत में लगातार हो रही बढ़ोतरी।

महंगे पेट्रोल-डीजल से महंगाई को न्योता

वर्ष	कच्चा तेल	पेट्रोल	डीजल
26 मई 2014	$109.1/बैरल	₹ 71.51	₹ 57.28
5 जुलाई 2021	$75.16/बैरल	₹ 99.92	₹ 89.42
अंतर	$33.94/बैरल(-)	₹ 27.69 (+)	₹ 32.14 (+)

नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री जब देश की सत्ता संभाली थी तब कच्चे तेल की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में ऊंचाई पर थी। उस मुकाबले आज इसकी कीमत 33.94 डॉलर प्रति बैरल कम हो चुकी है। मगर, पेट्रोल और डीजल की कीमत इस हिसाब से सस्ती नहीं हुई। उल्टे बढ़ती चली गयी। सरकार ने इस मद को राजस्व की कमाई का जरिया बना लिया।

महामारी की दूसरी लहर में लॉकडाउन के दौरान पेट्रोल-डीजल की खपत में 10.6 प्रतिशत की कमी आयी लेकिन इस दौरान राजस्व में 77 फीसदी की बढ़ोतरी हो गयी। पिछले साल जहां 2.2 लाख करोड़ रुपये राजस्व की वसूली हुई थी वहीं इस साल यह राजस्व 3.9 लाख करोड़ हो जाने का अनुमान है।

26 मई 2014 के मुकाबले पेट्रोल आज 27.69 रुपये प्रति लीटर और डीजल 32.14 रुपये प्रति लीटर महंगा हो चुका है। यह महंगाई नजरअंदाज करने वाली नहीं है। दरअसल पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमत ने देश में परिवहन से लेकर फल, सब्जियां और दैनिक उपभोग की दूसरी वस्तुओं की कीमत में भी आग लगा दी।

ज़ुबान पर झलकता है दर्द

1 मार्च 2014 को घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 410.5 रुपये थी। 1 जलाई 2021 को यही कीमत 834.5 रुपया हो चुकी है। यानी दोगुने से भी महंगी हो गयी घरेलू गैस। जाहिर है कि पेट्रोल-डीजल-घरेलू गैस की बेलगाम कीमत ने आम भारतीयों की मुश्किल बढ़ा दी है। औसत मध्यमवर्गीय परिवार में किचन का बजट जहां 8 हजार रुपये महीने हुआ करता था, वह 2014 के मुकाबले 2021 में 18 हजार हो चुका है। निम्न मध्यमवर्गीय परिवार में जो किचन 4 हजार रुपये में चल जाया करता था उसे अब 10 हजार रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं।

गाजियाबाद में मध्यमवर्गीय परिवार की अर्चना मिश्रा बताती हैं कि 7 साल पहले 400 रुपये की सब्जी 7 दिन चलती थी। मगर, आज 700 रुपये की सब्जी चार दिन नहीं चल पाती है। बरेली से देवेश गुप्ता बताते हैं कि सात साल पहले 100 रुपये के पेट्रोल से हफ्ते भर वे बाइक चला लेते थे। लेकिन, अब 300 रुपये का पेट्रोल भी कम पड़ जाता है। गाजीपुर से नीरज बताते हैं कि उनकी कार पहले 3200 रुपये में फुल हो जाया करती थी। आज इसके लिए साढ़े पांच हजार रुपये से ज्यादा लग जाते हैं।

महंगाई से सरकार क्यों नहीं बेचैन?

यह सवाल महत्वपूर्ण है कि महंगाई से जनता परेशान है लेकिन यह चिंता सरकार को बेचैन क्यों नहीं करती? इस सवाल के जवाब में आर्थिक मामलों के जानकार पूर्व आईआरएस अधिकारी कमल किशोर कठेरिया कहते हैं कि पहले महंगाई पर जनता प्रतिक्रिया देती थी। राजनीतिक दल आंदोलन करते थे। सरकार पर दबाव बनता था। अब महंगाई को लेकर सरकार बेफिक्र है। सत्ता को पहले की तरह राजनीतिक सेहत बिगड़ जाने का खतरा नहीं दिखता। आम लोगों ने भी खुद को किस्मत के हवाले कर दिया है। श्री कठेरिया कहते हैं कि कोरोना की महामारी भी विरोध करने वालों को ही महामारी एक्ट के तहत मजबूर करती है जो सरकार के लिए हथियार बन गयी है।

थोक बाजार चढ़ने से खुदरा बाज़ार भी उछल पड़ा

थोक मूल्य सूचकांक में बढ़ोतरी का असर खुदरा भाव पर बहुत ज्यादा हुआ है। महंगाई का असर खुदरा मुद्रास्फीति पर भी पड़ा है और यह बीते पांच महीने में सबसे ऊंचे स्तर 6.3 फीसद पर पहुंच गया है। यह आरबीआई की उम्मीद से 2.3 फीसदी ज्यादा है। केवल दाल, शक्कर, आटा, सरसो तेल की कीमत पर ध्यान दें तो बीते सात साल में इसमें बड़ा फर्क देखने को मिला है। दालों की कीमत डेढ़ से दो गुणा के करीब पहुंच गयी है तो सरसो तेल में दुगुने से भी ज्यादा उछाल देखने को मिला है। ये तो महज उदाहरण हैं। बाकी सामानों की कीमतों में भी ऐसी ही उछाल देखने को मिली है।

2014 और 2021 में कीमत की तुलना

	2014 (₹/किग्रा)	2021 (₹/किग्रा)
उड़द दाल	79.19	150.00
अरहर दाल	75.82	125.00
मूंग दाल	97.25	130.00
शक्कर	36.10	40.00
चना दाल	49.59	137.00
गेहूं का आटा	25.99	32.00
सरसो तेल	90.00	190.00

मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के आंकड़ों के मुताबिक खाद्य पदार्थों की कीमत में मई 2021 में बीते वर्ष इसी माह के मुकाबले 5.01 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। बीते छह महीने में यह सबसे ज्यादा है। इस दौरान तेल और घी की कीमतों में 30.84 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। वहीं पेय पदार्थों में 15.1 फीसदी, फलों में 11.98 फीसदी और दालों की कीमत में 9.39 फीसदी की रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गयी है।

महज नारों में है सबका साथ, सबका विकास

बुलेटिन ब्यूरो

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि कहने को सबका साथ, सबका विकास का नारा खूब लगाया जाता है लेकिन हकीकत में भाजपा केवल कुछ पूंजीपतियों का साथ करती है और उनके विश्वास पर ही काम करती है। जनसामान्य की तकलीफों को कम करने के बजाय वह उनमें और बढ़ोतरी करने की साजिशें करती रहती है। कृषि अर्थव्यस्था को बर्बाद करने के बाद अब वह घरेलू अर्थव्यवस्था को भी चौपट करने में लग गई है।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा जब से सत्ता में आई है, महंगाई विकराल बनती गई है। चारों तरफ इसके प्रसार से आम आदमी की तो कमर ही टूट गई है। महंगाई के जरिए भाजपा हर क्षेत्र में अभाव की स्थिति पैदा करने में लगी है ताकि लोग भूख, कुपोषण और बीमारी की वजह से काल कवलित होते रहें। उसका फार्मूला गरीबी हटाने के लिए गरीब को ही तबाह करने का है।

पेट्रोल-डीजल की दैनिक आवश्यकता है। इनके महंगा होने से दैनिक उपभोग की वस्तुएं भी स्वतः महंगी हो जाती हैं। कृषि और परिवहन के दामों में भारी वृद्धि से ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। किसान सिंचाई, खाद-बीज, कीटनाशक, कृषियंत्र व जुताई के बढ़े दामों से हुई परेशानी बता भी नहीं पाया कि उस पर बिजली की बढ़ी दरें थोप दी गईं।

डीजल की दर पिछले छह महीने में 40 फीसदी तक बढ़ गई हैं। इसकी तुलना में माल ढुलाई की दरों में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। माल भाड़ा बढ़ने से सब्जी-फल व अन्य सभी जरूरी वस्तुओं के दाम भी बढ़ गए हैं। पेट्रोल-डीजल के बढ़े दामों से परिवहन सेवाओं के भाड़े में भारी

महंगाई नहीं रह गयी समृद्धि का प्रतीक

पूर्व प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्री डॉ मनमोहन सिंह ने कभी कहा था कि महंगाई देश की समृद्धि का प्रमाण होती है। आज वे ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि आज आम लोगों की खरीदने की क्षमता घट चुकी है। यही वजह है कि महंगाई तो बढ़ रही है लेकिन न तो देश की जीडीपी बढ़ रही है और न ही राष्ट्रीय आय। बीते एक साल में जीडीपी का आकार 6.05 लाख करोड़ रुपये छोटा हो गया है।

महंगाई मनमोहन सिंह के जमाने में भी थी। मुद्रास्फीति की दर तब भी दहाई के अंक को

उछाल आया है। रसोई गैस के दामों में भी भारी वृद्धि कर दी गई है। सब्सिडी वाला गैस सिलेण्डर 25 से 50 रुपये महंगा हो गया है जबकि कामार्शिलय सिलेण्डर 84 रुपये महंगा हो गया है।

आरटीआई से मिली सूचना के अनुसार पेट्रोलियम उत्पादों से भारत सरकार को 4.51 लाख करोड़ रुपये का फायदा हुआ है। इन सबके बीच जनता पिसती रही है। खाद्य वस्तुओं की महंगाई से लोगों की पौष्टिक भोजन में कटौती करनी पड़ती है। नतीजा कुपोषण और भूख से गरीब आदमी की मौत होना स्वाभाविक है।

श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि विशेषज्ञों की राय है कि देश में महंगाई का दौर अभी थमने वाला नहीं है। वैसे भी कोरोना महामारी से कई सामाजिक-आर्थिक संकट पैदा हुए हैं। उद्योग-धंधों के बंद होने से बेरोजगारी बढ़ी है। लोगों की आय घटी है। भाजपा सरकार ने बड़े लोगों को कई राहतें दी हैं पर जनसामान्य की तकलीफों पर उसने निगाह भी नहीं डाली है।

पार कर चुकी थी, लेकिन तब आम लोगों के पास इस महंगाई से जूझने के लिए पैसा था। आज स्थिति उलट है। महंगाई तो बढ़ रही है लेकिन न प्रति व्यक्ति आमदनी में इजाफा हो रहा है और न ही रोजगार बढ़ रहे हैं। इस वजह से आम लोगों के हाथों से नकद निकलता चला जा रहा है और वे महंगाई से जूझने की स्थिति में नहीं हैं। महंगाई समृद्धि के बजाए बेबसी का प्रतीक बन गयी है।

2004-2014 के दस साल में जहां 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे थे, वहीं मोदी सरकार में सिर्फ वर्ष 2020 में 23 करोड़ लोगों की दैनिक आमदनी न्यूनतम मजदूरी से भी कम हो गयी। इस स्थिति में महंगाई ने गरीब लोगों पर कहर बरपा दिया है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की सर्वे रिपोर्ट कहती है कि 90 फीसदी लोगों ने जवाब दिया कि लॉकडाउन का असर परिवार पर पड़ा। थाली में भोजन कम हो गये। खाना-पीना कम हो गया। यह स्थिति भयावह है।

महंगाई ने थाली से भोजन छीन ली है। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। फौरन आम लोगों के हाथों में नकदी उपलब्ध करायी जानी चाहिए। छोटे-मझोले उद्योग और कारोबार से जुड़े लोगों को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए कदम उठाना भी उतना ही जरूरी है। यह अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिहाज से भी जरूरी है और रोजगार पैदा करने के ख्याल से भी। महंगाई डायन हो या लायन- इसका मुकाबला करने के लिए आम लोगों को सशक्त बनाना होगा और यह काम सरकार ही कर सकती है।

(यह लेखक के अपने विचार हैं)

जीएसटी के खिलाफ आक्रोश दिवस

बुलेटिन ब्यूरो

समाजवादी व्यापार सभा ने जीएसटी के 4 वर्ष पूरा होने पर 30 जून 2021 को प्रदेश स्तर पर आक्रोश दिवस मनाया और सभी 75 जिलों की 97 जिला व महानगर इकाइयों ने जीएसटी को व्यापारी विरोधी बताते हुए काली पट्टी बांधकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम संबोधित ज्ञापन जिला मुख्यालय में दिया। ज्ञापन के माध्यम से पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाने, जीएसटी के तीन स्लैब बनाने, उत्तर प्रदेश में अभी तक लगभग 4 हजार करोड़ से ज्यादा फंसे जीएसटी रिफंड को वापस करने तथा जीएसटी में गिरफ्तारी का प्रावधान हटाने की मांग की गई है। ज्ञापन में जीएसटी के रिटर्न एवं आयकर समेत अन्य विभागों के रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने, जीएसटी पोर्टल पर होलसेलर व रिटेलर दोनों के लिए एक और कॉलम बनाने, जीएसटी ऐक्ट में जुर्माना और पेनाल्टी में से एक को समाप्त करने और बिना नोटिस कोई पेनाल्टी न लगाने की भी मांग की गई है।

सहारनपुर में प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक श्री संजय गर्ग, कानपुर में प्रदेश महासचिव अभिमन्यु गुप्ता, लखनऊ में प्रदेश उपाध्यक्ष पवन मनोचा व यासिर सिद्दीकी, झांसी में प्रदेश उपाध्यक्ष अजय सूद, वाराणसी में प्रदीप जायसवाल, प्रयागराज में दुर्गा प्रसाद गुप्ता, अलीगढ़ में अतीत अग्रवाल, औरैया में मनोज पोरवाल व कन्नौज में अंशुल गुप्ता के नेतृत्व में जिला व महानगर कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने विसंगतिपूर्ण व व्यापारी विरोधी जीएसटी के खिलाफ आक्रोश दिवस मनाते हुए ज्ञापन सौंपा।

उल्लेखनीय है कि भाजपा राज में दुकानदारी, कारोबार, व्यापार सभी बर्बाद हो गए हैं। करोड़ों व्यापारी भाजपा की गलत आर्थिक नीतियों के शिकार हुए हैं। नोटबंदी, जीएसटी से परेशान व्यापारियों की हालत लॉकडाउन ने बुरी तरह बर्बाद की है। संवेदनहीन भाजपा सरकार में व्यापारी घर के गहने जेवर गिरवी रखने को मजबूर हो गए है। उस पर तमाम पाबंदियां लगाकर उसे अपमानित-लांछित भी किया जा रहा है।

मुरादाबाद के पीतल कारोबार की सांसें टूटती जा रही हैं। कोरोना कर्फ्यू, ऑक्सीजन की किल्लत, कच्चे माल की बदली कीमतों की वजह से इस धंधे में बहुत नुकसान हो चुका है। फर्नीचर कारोबारियों का भी बुरा हाल है।

कोरोना संकट की वजह से लगे लॉकडाउन और कर्फ्यू के दौरान अकेले राजधानी लखनऊ में करीब सवा लाख छोटे-बड़े कारोबारियों को 50 दिनों में कई हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।

दरअसल भाजपा राज में छोटे दुकानदारों की कोई सुनने वाला नहीं है। ठेला, पटरी पर छोटा मोटा सामान बेचने वालों को कोई राहत नहीं मिली। सरकार ने उन्हें 10 हजार रुपए दिलवाने का वादा किया पर मिला धेला भी नही। भाजपा सरकार की व्यापारी विरोधी नीतियों से सब तरह त्राहि-त्राहि मची हुई है।

भाजपा सरकार में छोटे दुकानदारों को धोखा मिला है जबकि चुनिंदा कॉरपोरेट घरानों को सभी सहूलियते देकर उनकी आमदनी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ाई गई है। व्यापारी समाज जान गया है कि भाजपा छोटे लोगो की नहीं बड़े पूंजी घरानों के हितों का पोषण करने वाली पार्टी है। व्यापारी 2022 में भाजपा को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी में है यह समाज समझ चुका है कि भाजपा राज में उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। छोटे व्यापारियों, दुकानदारों, ठेली पटरी सहित छोटा छोटा कारोबार करने वालों का भरोसा समाजवादी पार्टी पर है।

आजीवन प्रतिबद्ध समाजवादी रहे

राम शरण दास

बुलेटिन ब्यूरो

समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय श्री राम शरण दास की जयंती पर 3 जुलाई 2021 को समाजवादी पार्टी मुख्यालय में उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई।

श्री राम शरण दास आपातकाल के विरोध में जेल यात्री रहे। पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव 'नेता जी' के मंत्रिमंडल में वे कैबिनेट मंत्री रहे थे।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने श्री राम शरण दास के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कहा कि श्री राम शरण दास जीवन भर समाजवादी आंदोलन से जुड़े रहे। वे निष्ठा के साथ समाजवादी विचारधारा के लिए प्रतिबद्ध रहे।

इस अवसर पर श्री राम शरण दास के चित्र पर सर्वश्री राजेन्द्र चौधरी राष्ट्रीय सचिव, बलवंत सिंह रामूवालिया पूर्व मंत्री एवं अरविन्द कुमार सिंह, उदयवीर सिंह, जगजीवन प्रसाद एमएलसी गण ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए।

साफ़ और बेबाक

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

Socialist Leader of India. Chief Minister of UP (2012 - 2017)

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

कुछ लोग न जाने क्यों अपना ईमान इस हद तक गिरा देते हैं,
आस्था के चंदे और देश की रक्षा के सौदों में भी कमा लेते हैं!

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

पहले हाथरस की बेटी और अब लखीमपुर खीरी की बहन के साथ हुआ अत्याचार जनता देख रही है। रामायण साक्षी रही है और महाभारत गवाह है, जो नारी का अपमान करते हैं, उनको इस देश के लोगों ने कभी माफ़ नहीं किया और न कभी करेंगे।

भाजपा की सत्ता की भूख आसुरिक है।

#नहीं_चाहिए_भाजपा

Translate Tweet

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

आज प्रदेश भर में नाकाम भाजपा सरकार की जनादेश की 'चुनावी-चोरी', चंदा-चोरी, कोरोना-बदइंतज़ामी, किसान व नारी-उत्पीड़न, बेक़ाबू महँगाई, रिकार्ड बेरोज़गारी, ठप्प काम-धंधे के ख़िलाफ़ किए गए सपा के प्रदर्शन में मिला अभूतपूर्व समर्थन बता रहा है कि 2022 में 'आ रही है सपा और भाजपा साफ़'।

Translate Tweet

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

अपने 'राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल' धौलपुर के फाइटर पायलट बने छात्रों को हार्दिक बधाई!

इसी स्कूल में अनुशासन का पाठ भी पढ़ा और देश की सेवा का भी, जो आज भी मार्गदर्शक है और हमेशा रहेगा...

Translate Tweet

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

पुलित्ज़र पुरस्कारी पत्रकार और फोटोग्राफर दानिश सिद्दीक़ी की हत्या की ख़बर सुन कर अफ़सोस हुआ।

उनकी तस्वीरों ने जनता के विवेक को झिंझोड़ने का काम किया और उन्होंने काम के माध्यम से यह दिखाया कि निडर हो कर पत्रकारिता कैसे की जाती है।

#DanishSiddiqui

Translate Tweet

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

उप्र में भाजपा सरकार के कृपापात्र बने कुछ पुलिसकर्मियों के दुर्व्यवहार से प्रदेश की समस्त पुलिस की छवि धूमिल होती है.

भाजपा के शासन में दुशासन की कमी नहीं.

घोर निंदनीय!

#नहीं_चाहिए_भाजपा

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

इतनी बड़ी संख्या में मंत्री या मंत्रालय बदलने से भाजपा सरकार ने ख़ुद स्वीकार कर लिया है कि वो हर क्षेत्र में नाकाम रही है।

ज़रूरत केवल डिब्बे नहीं पूरी ट्रेन को बदलने की है।

भाजपा ने सरकार चलाने का नैतिक अधिकार खो दिया है।

देश-प्रदेश में बदलाव की लहर है।

#नहीं_चाहिए_भाजपा

Following

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रो. रामगोपाल यादव जी को जन्मदिन की अनंत शुभकामनायें।
@proframgopalya1

Translate Tweet

Akhilesh Yadav @yadavakhil... · 30 Jun

आज की विघटनकारी-रूढ़िवादी नकारात्मक राजनीति सत्ता के विरुद्ध एकजुट शोषित, उपेक्षित, उत्पीड़ित, अपमानित दलित, दमित, वंचित, ग़रीब, किसान, मज़दूर, महिला व युवाओं की 'नयी राजनीति' जन्म ले रही है।

2022 में उप्र में चुनाव नहीं लोकतांत्रिक क्रांति होगी।

Akhilesh Yadav

जन्मदिन की बधाई देने वाले सभी लोगों को हार्दिक धन्यवाद।

सपा के नेताओं, कार्यकर्ताओं व समर्थकों ने आज दो दिन भी समाज की सेवा के लिए समर्पित कर सराहनीय कार्य किया है। इन सभी से जनसेवा के इन चार सूत्रों पर चलने की अपील है. 'संपर्क, संवाद, सहयोग, सहायता'

नयी हवा है ~ नयी सपा है

Akhilesh Yadav

लोकप्रिय भोजपुरी फ़िल्म अभिनेता व गायक खेसारी लाल यादव से हुई मुलाक़ात और 'बाइस में बाइसिकल' के संकल्प की बात।
@khesariLY

#बाइस_में_बाइसिकल

Translate Tweet

पंजीकृत डाक पंजीकरण संख्या GPO/LW/NP-300/2021-2023 कुल पृष्ठ : 52 डिस्पैच तिथि : 15, 16, 17

समाजवादी पार्टी

चार सूत्रों में है जनसेवा का रास्ता
संपर्क, संवाद, सहयोग, सहायता